ध्येयIAS®
most trusted since 2003

नवंबर | 2023

ग्रामीण भारत में प्रतिभा

परीक्षोपयोगी सारगर्भित नोट्स

सरल व बोधगम्य भाषाशैली का उपयोग

डायग्राम, टेबल व चित्रों का तार्किक उपयोग

ध्येय IAS
कुरुक्षेत्र ज़िस्ट

ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभा को बढ़ावा

भूमिका

- ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता न केवल एथलीटों को सशक्त बना रही है, बल्कि शहरी-ग्रामीण विभाजन को समाप्त करने के साथ-साथ समुदायों के कल्याण को भी बढ़ावा दे रही है। नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध ये प्रयास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ग्रामीण युवाओं को एक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा स्वस्थ और अधिक संतुष्टिदायक कार्यों की ओर उन्मुख होती है।

पृष्ठभूमि

- ग्रामीण भारत में खेल लंबे समय से रोजमर्रा की जिंदगी का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। भारत में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवारी और रथदौड़ सहित खेलों के कई उदाहरण है। तीरंदाजी हमेशा से एक बहुत लोकप्रिय खेल रहा है, जिसका इतिहास महाभारत काल से है, यह उस काल के प्रमुख युद्ध कौशलों में से एक था।
- आज हमारे देश को विश्व चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय जीत हासिल हुई है। हाल ही एशियाई खेल 2022 में महिला तीरंदाजों ने 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीत कर हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया।
- इसके अलावा एशियाई खेलों में, पारुल चौधरी ने जापान की शीर्ष धाविका रिरिका हिरोनाका के विरुद्ध अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। इस हृदयस्पर्शी क्षण में, उन्होंने हिरोनाका को पराजित कर 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता । यह पारुल का खेलों में दूसरा पदक था। 28 वर्षीय एथलीट पारुल उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उनके पिता मेरठ के पास इकलौता गाँव के एक छोटे किसान है।
- ग्रामीण भारत की ये युवा लड़कियां और महिलाएँ सफल होने के लिए कई चुनौतियों का सामना करती है। इन महिला तीरंदाजों ने पितृसत्ताओं के दृष्टिकोण को बदल दिया है, कई लैंगिक समानता की पैरोकार बन गई हैं और खेलों में लड़कियों को बढ़ावा दे रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को मजबूत करने की सरकार की पहल

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल महासंघों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विश्वविद्यालय संघ जैसे विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन संगठनों के सहयोग से, राष्ट्रीय स्तर की बहु-खेल प्रतियोगिताओं जैसे खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करता है। अब मंत्रालय शीघ्र ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन भी करने जा रहा है।
- **खेलो इंडिया योजना**
  - इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अपने पांच ऐसे कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देते हैं।
  - यह राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल का प्रदर्शन करने और प्रतिभा तलाशने का बुनियादी मंच है।
  - इस योजना के 'टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट' घटक के तहत, एथलीटों का चयन कर प्रति एथलीट प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - इस योजना का विशेष बल 'ग्रामीण, स्वदेशी और जनजातीय खेलों (मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलंबम आदि) को बढ़ावा देने' पर है, ताकि इन खेलों को लोकप्रिय बनाया जा सके।
  - खेलो इंडिया योजना के घटक 'अस्मिता लीग' में विभिन्न खेल स्पर्धाओं की लीग आयोजित की जाती है जो भारत की महिला एथलीटों में मजबूती, दृढ संकल्प और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देती हैं। इसका नाम अस्मिता 'अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाई इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन' (ASMITA) सशक्तीकरण और प्रेरणा का प्रतीक है।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायता से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), एसएआई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी का विस्तार केंद्र, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) [नियमित स्कूलों, स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट (आईजीएमए) स्कूल और अखाड़ों के लिए अपनी उप-योजनाओं के साथ] के माध्यम से देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाएं लागू की है।

- सांसद खेल और सांसद खेल महाकुंभ के रूप में प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इंडोर और आउटडोर खेल कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- **उन्नयन खेलो इंडिया योजना**
    - खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण हेतु सरकार का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में खेल के बुनियादी ढांचे में समग्र परिवर्तन करना है। शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड आवंटित किए जा रहे है।
    - वर्ष 2016-17 से पूरे देश में खेल बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने के लिए खेलो इंडिया योजना के 'खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन' हेतु लगभग 2741 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
    - **उदाहरण:**
        - मेडक जिले में 5.47 करोड़ रुपये की लागत से एक सिंथेटिक ट्राथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है जो उत्तरी तेलंगाना में स्थित है।
        - राजस्थान के जिल में एक बहुद्देश्यीय हॉल बनाया गया है जिससे ग्रामीण राजस्थान में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- यह विश्वस्तरीय स्टेडियमों, स्विमिंग पूल, प्रशिक्षण केंद्रों, एथलेटिक ट्रैक और बहुद्देशीय हॉल के विकास को सक्षम बनाता है, जिससे इच्छुक एथलीटों के लिए अपने कौशल को सुधारने और खेल जगत में समृद्ध होने के अवसर सृजित होते हैं।

नशीली दवाओं के सेवन के विरुद्ध उत्प्रेरक

- युवाओं को खेलों में शामिल करने से महत्वपूर्ण सामाजिक- आर्थिक लाभ मिलते हैं। साथ ही, यह देश के ग्रामीण हिस्सों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार, खेलों में निवेश करने से न केवल कुशल एथलीट तैयार होते हैं बल्कि जिम्मेदार, लचीले और नशामुक्त व्यक्तियों का भी विकास होता है, जो समाज में सार्थक योगदान देते हैं।

भारत को गौरवान्वित करती महिला एथलीट

- एशियाई खेल 2022 में भारत ने 2018 की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक स्वर्ण पदकों के साथ 60 वर्षों में अपने सर्वोच्च पदक (107) प्राप्त किए। इस टूर्नामेंट में महिला एथलीटों ने भारतीय दल के कुल पदकों में से लगभग 50% पदक जीते।
- **रोशिबिना देवी:**
    - मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के एक शांत गाँव क्वाकसिफाई मयई लीकाई की निवासी।
    - उपलब्धि:पारंपरिक मणिपुरी मार्शल आर्ट 'धांग-ता' से शुरुआत करते हुए, वुशू में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते।
    - 2018 एशियाई खेलों में महिलाओं की 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
    - 2022 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता, जो एशियाई खेलों में वुशु में भारत का पहला रजत पदक था।

निष्कर्ष

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न ग्रामीण एथलीटों और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत को गौरवान्वित करने वाली महिला एथलीटों को बढ़ावा देने से खेल प्रतिभाओं के विकास और प्रतिस्पर्धा की नई संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की प्रतिबद्धता न केवल एथलीटों को सशक्त बना रही है बल्कि शहरी-ग्रामीण विभाजन को समाप्त कर समुदायिक कल्याण को भी बढ़ावा दे रही है। इस प्रकार सरकार के सहयोग और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प से प्रेरित यह परिवर्तन न केवल अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है बल्कि एक स्वस्थ, अधिक सक्रिय और अधिक एकजुट समाज का भी निर्माण करता है।

पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों का सशक्तीकरण

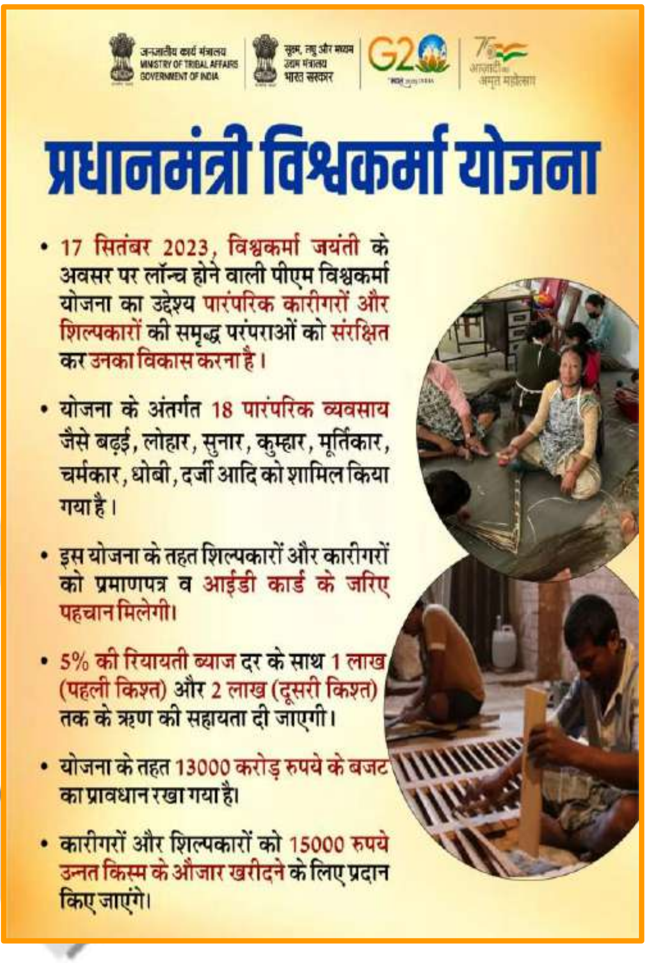
जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार
G20
आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

- 17 सितंबर 2023, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च होने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित कर उनका विकास करना है।
- योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, धोबी, दर्जी आदि को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाणपत्र व आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी।
- 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख (पहली किश्त) और 2 लाख (दूसरी किश्त) तक के ऋण की सहायता दी जाएगी।
- योजना के तहत 13000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है।
- कारीगरों और शिल्पकारों को 15000 रुपये उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए प्रदान किए जाएंगे।

परिचय

- ग्रामीण भारत, जिसे अक्सर राष्ट्र की कृषि रीढ़ कहा जाता है, अप्रयुक्त संभावनाओं और पारंपरिक प्रतिभा का विशाल भंडार है। अतः ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना न केवल पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करना है बल्कि ग्रामीण भारत में अनगिनत परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ भी करता है।
- इसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति तेज़ी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ सकें। यह योजना एक आशाजनक युग तथा परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री का न केवल उत्सव मनाया जाता है बल्कि इसे आगे बढ़ाकर समृद्ध भविष्य की ओर ओर ले जाया जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- पारंपरिक शिल्प कारीगर गतिविधियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ये कलात्मक अभिव्यक्तियाँ न केवल सौन्दर्य की दृष्टि से मूल्यवान हैं बल्कि भारत की विरासत को संरक्षित करने का भी अभिन्न अंग हैं।
- ये कारीगर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 'विश्वकर्मा' कहा जाता है। जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के सृजक और निर्माता हैं।
- केंद्र सरकार ने 17 सितंबर, 2023 को यशोभूमि, दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। भारत में विश्वकर्माओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की समीक्षा

- वर्तमान में लगभग 20 केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं है जो देशभर के कारीगरों को सहयोग देने और सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं:
  - वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम क्रमशः हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें ऋण, विपणन, टूलकिट, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करते हैं।
  - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "पीएम स्वनिधि" के तहत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों/फेरीवालों को ब्याज सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है।
  - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी) के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
  - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण स्वरोज प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना।आदि।

- राज्य सरकारों द्वारा समर्थित योजना
  - **उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना:** टोकरी बुनकरों, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई आदि जैसे व्यवसायों में लगे कारीगरों को ऋण, आधुनिक टूलकिट और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है।
  - **गुजरात सरकार की श्री वाजपेयी बैंकेबल योजना**: कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के कारीगरों/ शिल्पकारों को रियायती ऋण प्रदान करती है।
  - **गुजरात सरकार की दत्तोपंत थेंगड़ी कारीगर ब्याज सब्सिडी योजना:** गुजरात के पारंपरिक शिल्प, कला, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता के साथ-साथ ऋण सहायता भी प्रदान करती है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:

- **पहचान:** पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान।
- **कौशल उन्नयन:** 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण।
- **टूलकिट प्रोत्साहन:** बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रु. रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
- **ऋण सहायता:** बिना कुछ गिरवी रखे 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में तीन लाख रुपए तक का ऋण एक लाख और दो लाख रुपए के दो किश्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ प्रदान किया जाएगा।
- **डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:** प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेनदेन एक रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।
- **विपणन सहायता:** मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर मौजूदगी, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

कारीगरों और शिल्पकारों को सहयोग देने की इस योजना की रूपरेखा उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में भी लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। कारीगर और शिल्पकार अपनी रचनात्मकता और कौशल के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवेश में योगदान देकर एक सक्षम वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। यह योजना एक आशाजनक युग का प्रतीक है जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध 'टेपेस्ट्री' का न केवल उत्सव मनाया जाता है बल्कि इसे आगे बढ़ाकर समृद्ध भविष्य की ओर ले जाया जाता है, जो परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेशन

परिचय

- किसी सी भी देश का सामाजिक- आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है, कि वहां विज्ञान-तकनीक के क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार निरंतर नवाचारों को कितना बढ़ावा दिया जाता है। अतः शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार का आधार बनाना चाहिए । आज शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हँड होल्डिंग तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को एकीकृत करने के सभी प्रयासों के फलीभूत होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित सभी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन की कल्पना करती है ताकि इसे अधिक शिक्षार्थी केंद्रित, लचीला और प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जा सके। यह रेखांकित करती है कि 'शिक्षा के कई पहलुओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और समावेशन का समर्थन किया जाएगा और अपनाया जाएगा'।
- इसके लक्ष्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने और 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।
- एनईपी 2020 के अनुसार भारत में, 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित हो, जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित हो।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

- **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR):**
    - एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यह जुलाई 2021 में स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में लॉन्च किया गया था।
    - इसमें शिक्षण सुविधा हेतु लाइव कक्षाएं, ईटीबी से जुड़ी आदर्श सामग्री, डिजिटल पाठ्यक्रम, मल्टी चैनल चैटबॉट, सहयोग आदि शामिल है।

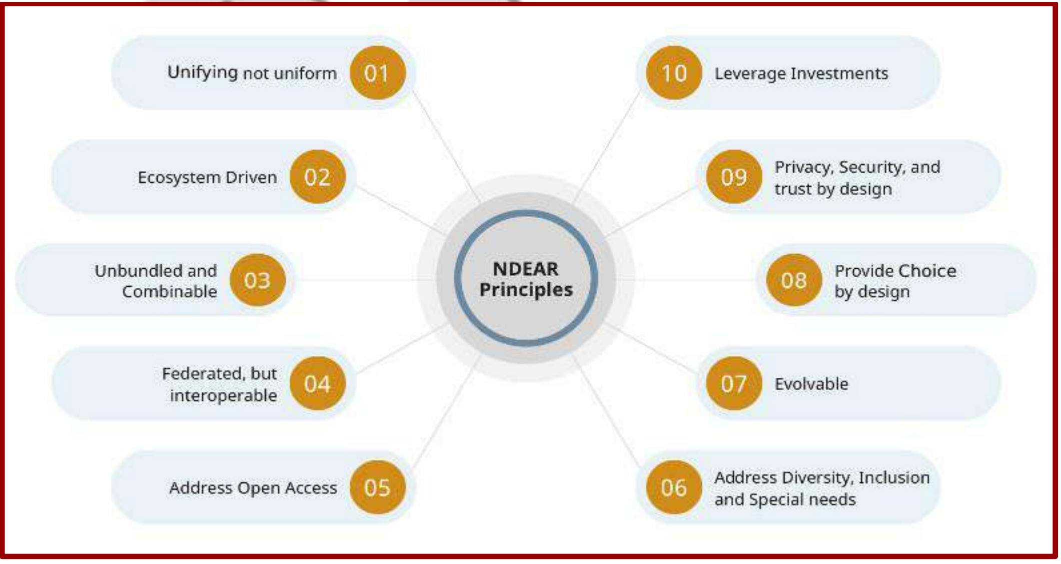
NDEAR Principles
Unifying not uniform 01
Ecosystem Driven 02
Unbundled and Combinable 03
Federated, but interoperable 04
Address Open Access 05
06 Address Diversity, Inclusion and Special needs
07 Evolvable
08 Provide Choice by design
09 Privacy, Security, and trust by design
10 Leverage Investments

- **दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा):**
    - शिक्षा मंत्रालय ने दीक्षा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्रियों तक पहुँच प्रदान करता है। इसमें एआई-सक्षम तारा चैटबॉट सहित एनडीईएआर बिल्डिंग ब्लॉक श्रेणियां भी शामिल हैं।
    - यह इंटरेक्टिव पाठ योजना, परीक्षण और अन्य शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। दीक्षा एक 'मेड इन इंडिया' डिजिटल बुनियादी ढांचा है और इसे पीएम ई-विद्या पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्कूली शिक्षा के लिए 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' के रूप में विकसित किया गया है।

- **विद्या समीक्षा केंद्र**
    - छात्रों के नामांकन, उनके सीखने के स्तर में प्रगति, स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने, पाठ्यपुस्तक वितरण, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा आवश्यक सहायता आदि पर नजर रखने के लिए राज्य और केंद्रीय, दोनों स्तरों पर विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) स्थापित किए गए हैं।
    - इनका उद्देश्य पहले से उपलब्ध डेटा सेट जैसे यूडीआईएसई, छात्र डेटाबेस, एनएएस, शिक्षक डाटाबेस, दीक्षा, निष्ठा, आदि को एकीकृत करके डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
    - उपयोगकर्ताओं को अपने राज्य के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कॉन्फ़िगर करने में मदद करने के लिए, एनसीईआरटी ने एक पूर्व-कॉन्फ़िगर पैकेज विकसित किया है, जिसे मौजूदा कार्यक्रमों के साथ अनुकूलित और एकीकृत किया जा सकता है।
- **स्वयम**
    - यह एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो शिक्षकों के लिए भी मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले, इंटरेक्टिव और सुलभ ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है।
    - यह देश का एमओओसी प्लेटफॉर्म है जो विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर प्रदान करता है।
    - एनआईओएस और एनसीईआरटी 'स्वयम' के तहत स्कूल क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है, जो 9वीं से 12वीं तक स्कूल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
    - 'स्वयम' एक अन्य सरकारी पहल 'स्वयं प्रभा' के साथ जुड़ा हुआ है जो डीटीएच चैनलों के माध्यम
    - से शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। यह सीमित इंटरनेट एक्सेस वाले छात्रों को पाठ्यक्रमों से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल)**
    - राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) शिक्षा मंत्रालय की शैक्षिक सामग्री और संसाधनों का एक डिजिटल भंडार है।
    - एनडीएल की मदद से, छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधनों की एक व्यापक लाइब्रेरी तक पहुँच होगी।
    - यह प्लेटफ़ॉर्म ओपन-एक्सेस है और उपयोगकर्ता शुल्क के बिना अपने संसाधनों तक पहुँच सकते है।
    - एनडीएल भारत में डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और डिजिटल इंडिया अभियान और स्वयम जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ जुड़ा हुआ है।
- **निष्ठा (NISHTHA)**
    - इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2019 में शुरू किया गया।
    - यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो शिक्षण में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित शिक्षाशास्त्र के विभिन्न पहलुओं में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित करता है।
    - एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के साथ, 'निष्ठा' को शिक्षकों के सभी स्तरों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।
- **स्कूल इनोवेशन काउंसिल**
    - शिक्षा मंत्रालय द्वारा 6 से 12 मानकों के साथ डिजाइन स्कूल इनोवेशन काउंसिल स्कूलों में विचारधारा, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के लिए; स्कूल इनोवेशन एम्बेसेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एसआईएटीपी), की एक पहल है।
- **एसआईएटीपी (SIATP)**
    - यह कार्यक्रम स्कूल के शिक्षकों को विचारधारा और नवाचार पर छात्रों को सलाह देने और प्रशिक्षण देने के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के बीच लीक से हटकर सोच को बढ़ावा देना और शिक्षकों को सलाह-कौशल से लैस करना है।

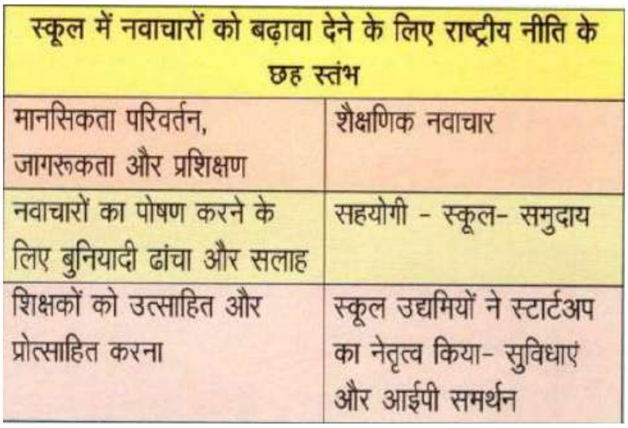

स्कूल में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति के छह स्तंभ	
मानसिकता परिवर्तन, जागरूकता और प्रशिक्षण	शैक्षणिक नवाचार
नवाचारों का पोषण करने के लिए बुनियादी ढांचा और सलाह	सहयोगी - स्कूल- समुदाय
शिक्षकों को उत्साहित और प्रोत्साहित करना	स्कूल उद्यमियों ने स्टार्टअप का नेतृत्व किया- सुविधाएं और आईपी समर्थन

  - यहाँ एक डिजिटल मंच के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें पांच मॉड्यूल शामिल होते हैं- डिजाइन सोच और नवाचार, विचार पीढ़ी और विचारधारा, बौद्धिक संपदा अधिकार, वित्त, मानव संसाधन (एचआर) और बिक्री, उद्यमिता एवं प्रोटोटाइप।

आगे की राह

- वर्तमान भारत एक ऐसा वातावरण बनाकर की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए काम कर रहा है जो प्रतिभा पूल प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण उपकरणों और व्यापक क्षमता निर्माण समर्थन का उपयोग करने में शिक्षकों की मदद करता है। हालांकि ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को कम करना एक कठिन कार्य है जिसके लिए सार्वजनिक व्यापार और नागरिक समाज क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत है। जैसे:
  - **इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार** ।
  - **डिजिटल साक्षरता**।
  - शैक्षिक सामग्रीण की पर्याप्त उपलब्धता।
  - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)।
  - डिजिटल शिक्षा हेतु स्कूलों को डिजिटल संसाधनों से युक्त करना।,
  - ई-पुस्तकें और ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रदान करके ग्रामीण में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।
  - शिक्षक प्रशिक्षण: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
  - निगरानी और मूल्यांकन: डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से डिजिटल अंतर को पाटने में प्रगति की लगातार निगरानी करना।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार के लिए आधार बनाना चाहिए जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो। शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र को विकसित करने की महती आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और नवाचार की संस्कृति को एकीकृत करने के सभी प्रयासों के फलीभूत होने से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों सहित सभी छात्रों की क्षमताओं का समुचित उपयोग हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहन

परिचय

सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है।

सूक्ष्म उद्यमिता एक प्रकार का व्यवसाय है जो आमतौर पर एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म उद्यमों को आमतौर पर उनके निवेश, कर्मचारी संख्या और वार्षिक बिक्री के आधार पर परिभाषित किया जाता है।

- भारत लगभग 1.5 अरब लोगों का देश है, जहां परंपरागत भारता रूप से 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर रही है। लेकिन यह एक सुस्थापित तथ्य है कि आजीविका की दृष्टि से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता समाधान की बजाय समस्याएं अधिक पैदा कर रही है।
- उदाहरण के लिए, खेतों में मशीनों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की सीमित संभावनाएं, कम उपज के कारण मोल भाव न कर पाना, उत्पादन लागत में वृद्धि आदि।
- अमृतकाल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन हमारे सामने है। इसकेलिए भारत सरकार ने मिशन मोड में ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है।

"सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को रोज़गार प्रदान करना, ग्रामीण घरेलू आय में वृद्धि, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की दर को कम करना आदि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हैं जिन्हें देश सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त कर सकता है। परोक्ष रूप से, यह लगभग सभी मोर्चों पर समग्र कृषि परिदृश्य को लाभान्वित करने वाला है, जैसे कि बुआई, कटाई, गुणवत्ता सुधार, विपणन में प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि।"

ग्रामीण युवाओं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म उद्यमिता एक 'गेम चेंजर' के रूप में :

- **सूक्ष्म उद्यमिता का दायराः** परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम वे हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु. से अधिक नहीं है। सामान्यतः इसमें 10 से कम कर्मचारी होते हैं और यह सीमित क्षेत्र में काम करती है।
- **लचीलापनः** सूक्ष्म उद्यमी खुद को बाजार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाते हैं। वे बड़े संगठनों में अपनायी जा रही आम नौकरशाही प्रक्रियाओं के बिना निर्णय ले सकते हैं और परिवर्तन लागू कर सकते हैं।
- **रोजगार सृजन :** सूक्ष्म व्यवसाय के मालिक जब कर्मचारी रखते है या ठेके पर काम कराते हैं तो वे रोजगार सृजन करने में मदद करते हैं।
- **नवोन्मेषः** नई वस्तुएं, सेवाएं और अवधारणाएं अक्सर छोटी कंपनियों द्वारा बाजार में प्रस्तुत की जाती हैं।
- **स्थानीय आर्थिक विकासः** सूक्ष्म व्यवसाय अक्सर आपूर्ति, सेवाओं और श्रम के लिए क्षेत्र के विक्रेताओं का उपयोग करके और नागरिकों को कर्मचारियों के रूप में नियोजित करके समुदाय की अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं।
- **आत्मनिर्भरताः** सूक्ष्म कारोबार के मालिकों का अपनी कंपनियों और उनकी वित्तीय नियति पर अधिक प्रभाव होता है। वे बड़े व्यवसायों अथवा पारंपरिक रोजगार ढांचे पर कम निर्भर होते हैं, जिससे सशक्तीकरण और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।
- **विविधता :** सूक्ष्म फर्में अक्सर विशिष्ट बाजारों को लक्षित करती हैं और ऐसे विशेष सामान या सेवाएं प्रदान करती हैं जो बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती।

आज, भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र रखने पर गर्व करता है। देश में 60,000 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।

सूक्ष्म उद्यमिता की वृद्धि के लिए भारत सरकार के प्रयास:

एस्पायर - नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना :

- एस्पायर योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रही है।
- एस्पायर योजना के तहत, ग्रामीण उद्यमी कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, बागवानी, आदि जैसे क्षेत्रों में नवीन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। योजना उद्यमियों को व्यवसाय प्रबंधन, वित्त, विपणन, आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

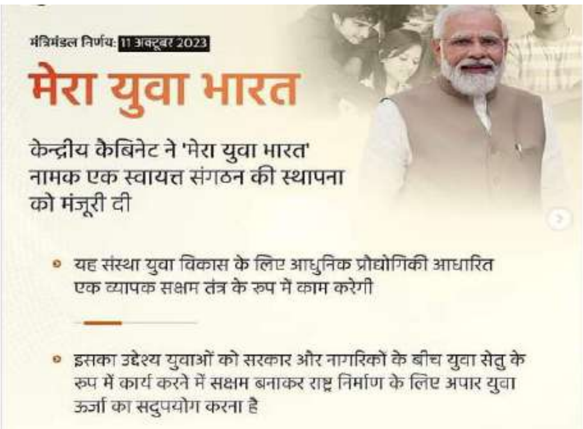

मंत्रिमंडल निर्णय: 11 अक्टूबर 2023

मेरा युवा भारत

केन्द्रीय कैबिनेट ने 'मेरा युवा भारत' नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना को मंजूरी दी

- यह संस्था युवा विकास के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप मे काम करेगी
- इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का सदुपयोग करना है

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा):

- नामक यह गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इस योजना के माध्यम से भारत में सूक्ष्म उद्यम बाजार के विस्तार में सहयोग करता है। मुद्रा सूक्ष्म इकाइयों को 10 लाख रु तक की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों और/या माइक्रोफाइनेंस संगठनों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।
- इन संपत्तियों को संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन (एसआईपी-ईआईटी) कार्यक्रम

- इसके तहत, भारतीय एमएसएमई और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विदेशी पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए सरकारी सहायता प्रदानकी जाती है ।
- इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी पेटेंट आवेदनों की लागत का 50% तक का भुगतान किया जाता है ।

गुणक अनुदान योजना (एमजीएस):

- इसका लक्ष्य कंपनियों को उत्पाद और पैकेज तैयार करने के लिए प्रमुख सरकारी और शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास समूहों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- वित्तीय सहायता: एक उद्योग को एक परियोजना के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं, जिसकी वांछित परियोजना अवधि 2 वर्ष से कम है। उद्योगों के एक समूह को तीन वर्ष की अवधि के दौरान 4 करोड़ रुपये तक दिए जा सकते हैं।

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई):

- इसकी स्थापना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए को है ।
- यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और सूक्ष्मफर्मों को काफी रियायती दरों पर और रेहन की आवश्यकता के बिना ऋण प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम प्रत्येक पात्र ऋण लेने वालों के लिए 200 लाख रुपये तक निधि और गैर-निधि- आधारित क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) :

- यह योजना लघु-स्तरीय क्षेत्र में की गई खरीदारी की संख्या को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। सरकार का निर्देश है कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यनों से ही करेंगे।
- साथ ही वस्तुओं की 358 श्रेणियां विशेष रूप से एमएसई से खरीदे जाने के लिए आरक्षित की गई हैं।

एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च या कोर रिसर्च ग्रांट (सीआरजी):

- सीआरजी का लक्ष्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों की सहायता करना है।
- यह स्थापित और उभरते दोनों शोधकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी, व्यक्तिगत-केंद्रित फंडिंग मॉडल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।

उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई अवधारणाओं और पहलों को प्रोत्साहित करना और सहयोग देना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
- यह चुनौतीपूर्ण सुझावों पर केंद्रित है जो यदि सफल होते हैं तो विज्ञान के लिए व्यापक रूप से लाभकारी हो सकते हैं।

डिज़ाइन क्लीनिक योजना:

- एमएसएमई मंत्रालय ने छोटी कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए नए और आविष्कारी डिजाइनों के साथ प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से एक स्थायी डिजाइन इको सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन क्लीनिक योजना शुरू की।
- इस कार्यक्रम के तहत डिजाइन सेमिनार में भाग लेने के लिए सरकार 60,000 रुपये तक तथा 3.75 लाख रुपये या सेमिनार के खर्च का 75% तक भुगतान करेगी, यदि सेमिनार किसी स्टार्टअप या एमएसएमई द्वारा आयोजित किया जाता है।

जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) योजना

- इसका उद्देश्य निर्माताओं को ऐसे बेहतर सामान बनाने के लिए प्रेरित करना है जो उच्च गुणवत्ता वाले, दोषमुक्त और विश्वसनीय हों।
- यह सहारा देने वाला (हैंडहोल्डिंग) कार्यक्रम है जो एमएसएमई को अत्याधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाने, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने और अपने सामान को लगातार बेहतर बनाने का मौका प्रदान करता है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में स्टार्टअप की संख्या और गतिविधि में काफी वृद्धि हुई है। 2023 तक, भारत में 60,000 से अधिक स्टार्टअप थे, और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण संबंधी प्रतिभा का विकास

परिचय

- भारत की ग्रामीण जनता के संदर्भ में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और पोषण में प्रतिभा को निखारना एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रौद्योगिकी एकीकरण, शिक्षा और सरकारी नीतियों जैसी रणनीतियों के माध्यम से, हम ग्रामीण समुदायों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आवश्यकताओं की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं।
- कृषि और आजीविका को सतत बनाने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को शुरू करने की आवश्यकता है।

भारत में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण युवा प्रतिभा का परिपोषण

- भारत अपनी विशाल ग्रामीण आबादी के साथ, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
- ग्रामीण युवा, जो कि देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु उचित दिशा देने और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथा सतत विकास हेतु मूल्यवान संसाधन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न एसडीजी को पूरा करने में ग्रामीण युवा निम्नलिखित प्रकार से योगदान दे सकते है:
  - **अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (एसडीजी 3):** ग्रामीण भारत में युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और समाज कल्याण के प्रति उनके रुझान को बढ़ाना चाहिए।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4):** ग्रामीण युवाओं को शैक्षिक पहलों में शामिल करके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर ज्ञान और जानकारी तक पहुँचने के लिए सशक्त बना सकते हैं जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और प्रासंगिक हो सकती है।
  - **लैंगिक समानता (एसडीजी 5):** युवा महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना और युवा पुरुषों को लैंगिक समानता के महत्व के बारे में शिक्षित करना, इस लक्ष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
  - **स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6):** ग्रामीण भारत अभी भी इस लक्ष्य से बेहद बेहद दूर है। ऐसे में युवाओं को इस संदर्भ में जागरूक करने और प्रशिक्षण के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।
  - **उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास (एसडीजी 8):** ग्रामीण युवा कृषि व्यवसाय और उद्यमिता में भाग लेकर आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ऋण तक पहुँच उन्हें स्थायी आजीविका और अपने क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान के लिए तैयार कर सकती है।
  - **असमानताओं में कमी (एसडीजी 10):** ग्रामीण युवाओं को सामुदायिक विकास परियोजनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करने से असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - **सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय (एसडीजी 11):** युवा पर्यावरण अनुकूल और सुनियोजित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे जिम्मेदार शहरीकरण को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकते हैं।

- **उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन (एसडीजी 12):** ग्रामीण युवा सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने और पर्यावरण- अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अपशिष्ट को कम करने, संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन कार्यवाई (एसडीजी 13)**: ग्रामीण युवाओं को पर्यावरण संरक्षण पहल, वृक्षारोपण अभियान और जलवायु जागरूकता अभियानों में शामिल करने से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। वे अपने समुदायों में जलवायु चैंपियन बन सकते हैं।
- **शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं (एसडीजी 16):** कानूनी जागरूकता और पक्षपोषण को बढ़ावा देकर, ग्रामीण युवा एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने में भूमिका निभा सकते हैं।
- **लक्ष्य हेतु भागीदारी (एसडीजी 17):** ग्रामीण युवा सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों-सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।

अभावों की संकेतकवार तुलना (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2023)

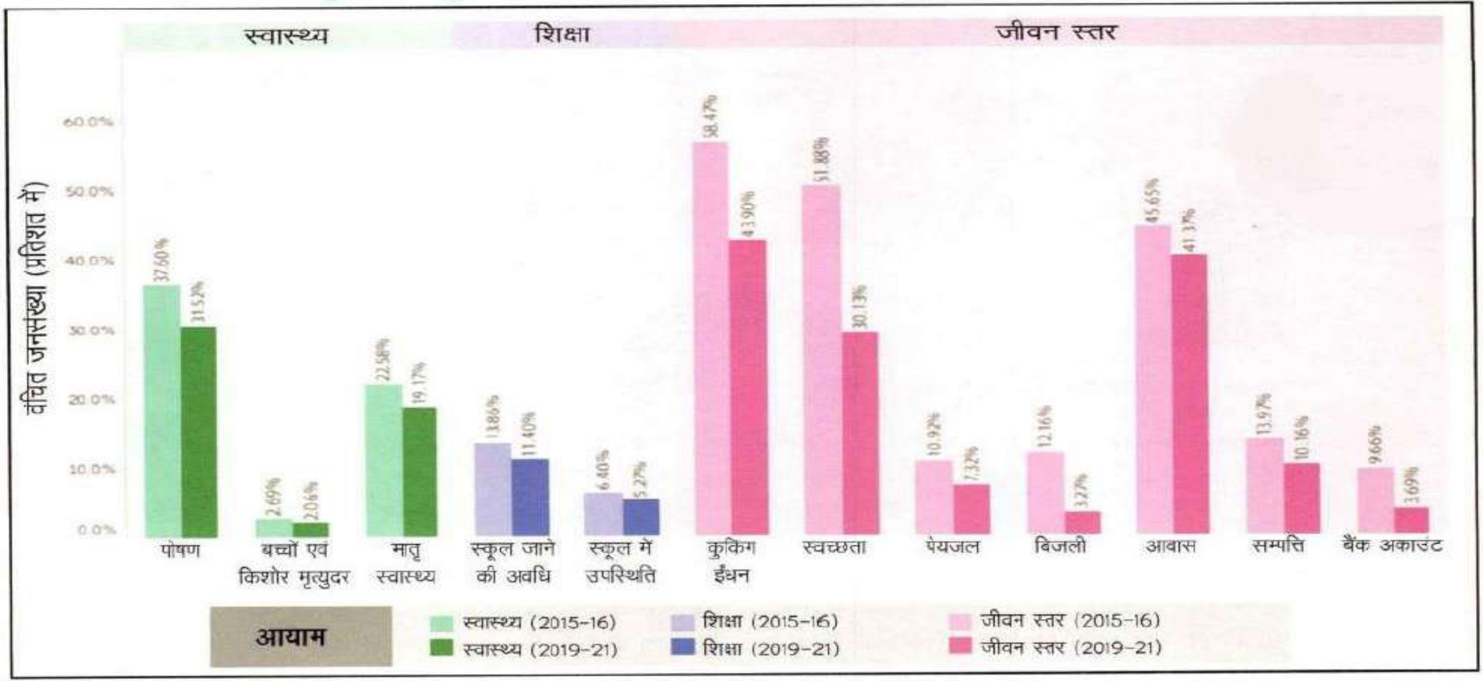

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी पहलें

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- पोषण अभियान
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना
- आकांक्षी जिलों के लिए परिवर्तन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएसपी)
- सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम

किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना

- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी)
- राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल
- निःशुल्क निदान पहल (एफडीआई)
- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं (एनएएस)
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ प्रमुख पहलें

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई)
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)
- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- लक्ष्य कार्यक्रम
- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल
- एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका
- देश भर में 25,000 से अधिक 'डिलीवरी पॉइंट' को मजबूत करना

इसके अतिरिक्त, मिशन परिवार विकास, मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा-आधारित नवजात देखभाल (एफबीएनसी), घर- आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और कार्यवाई से निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने जैसी पहल (SAANS), छोटे बच्चे के लिए घर आधारित देखभाल (HBYC), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), प्रारंभिक बचपन विकास (ECD), व्यापक गर्भपात देखभाल (CAC), पोषण पुनर्वास केंद्र (गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए एनआरसी) कार्यक्रम कार्यान्वयन में मदद दी जाती है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने, नए टीकों की शुरुआत के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

आगे की राह

ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना न केवल स्वास्थ्य और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में शामिल करने के व्यापक तरीके और साधन निम्नलिखित है:

- शिक्षा एवं कौशल विकास
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- ग्रामीण मेडिकल और नर्सिंग स्कूलों की स्थापना
- मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक
- सामुदायिक सहभागिता
- पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा
- डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता
- पोषण जागरूकता अभियान
- उद्यमिता और आर्थिक अवसर
- लैंगिक समानता और सशक्तीकरण
- सार्वजनिक निजी साझेदारी को प्रोत्साहन
- अनुसंधान और नवाचार
- पक्षपोषण और नीति प्रभाव

निष्कर्ष

ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में शामिल करना एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, सामुदायिक सहभागिता और आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है। ग्रामीण युवाओं को आवश्यक उपकरण और अवसर प्रदान करके, हम न केवल स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम लाने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से की क्षमता का भी उपयोग कर सकते हैं। युवाओं में निवेश, वर्तमान में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करके, जीवन भर इसे बढ़ाकर और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य में योगदान देकर तिगुना लाभांश प्राप्त कर सकता है।

प्रतिभाओं की खोज के लिए डाक नेटवर्क

परिचय

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए, एक बहुत बड़े जनसंख्या आधार में से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक व्यापक फ़लक वाले प्रतिभा खोजतंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके बाद प्रतिभाशाली और जन्मजात प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जानी चाहिए। जन्मजात प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा को राज्यों के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में निखारा जाना चाहिए।

डाकघर और ग्रामीण भारत

- **व्यापक डाक नेटवर्क:** भारतीय डाक विभाग के पास 1.59 लाख से अधिक डाकघर हैं, जो देश के कोने-कोने तक फैले हुए हैं। यह देश की एकमात्र संस्था है जो देश के कोने-कोने में मौजूद है।
- **प्रौद्योगिकी में प्रगति**: भारतीय डाक विभाग ने आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के माध्यम से अपने डाकघरों को आधुनिक बनाया है। अब सभी डाकघरों को नेटवर्क किया गया है और सभी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं।
- **बैंकिंग सेवाएं:** भारतीय डाक विभाग ने डाकघर बचत योजना, कोर बैंकिंग समाधान और जन सुरक्षा योजनाओं जैसे बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच को बढ़ाया है।
- 2014 के बाद से डाकघर बचत योजना के तहत बकाया शेष 6.19 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.34 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- 2015 में डाकघर बचत खाताधारकों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के साथ-साथ अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी जन सुरक्षा योजनाएं शुरू की गईं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी)

- डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 650 शाखाओं और 1.44 लाख एक्सेस प्वाइंटों के माध्यम से 'द्वार पर बैंकिंग सेवाएं' भी मुहैया कराता है, जो पूर्णतः कागजरहित बैंक है और विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है।
- 6.64 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें 78% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 47% खाते महिलाओं के नाम हैं।
- लगभग 84 लाख महिला ग्राहकों को उनके खातों में 3519 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) प्राप्त हुआ है।
- 15.09 लाख से अधिक खाते स्कूली छात्रों के लिए खोले गए हैं।
- अब तक, आईपीपीबी ने 380.25 करोड़ लेन-देन कार्य किए हैं, जिसमें 4.72 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन शामिल हैं।
- 70% से अधिक लेन-देन कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं द्वारा किए गए हैं।
- एईपीएस सेवा के माध्यम से, 9.90 करोड़ बैंक खातों से 29,162 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आहरित की गई है।
- कोविड महामारी के दौरान, एईपीएस ने पोस्टमैनों को 'ग्राहकों के द्वार' पर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी संवितरित करने में सक्षम बनाया।

डाकघर द्वारा संचालित योजनायें/ सेवाएं

- आईपीपीबी की हाल ही में शुरू की गई **अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना** एक दूरदर्शी एवं किफायती बीमा योजना हैजिसका लक्ष्य देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक कवरेज और सुरक्षा प्रदान करना है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की प्रायोगिक शुरुआत 8 जुलाई, 2023 को गुजरात के नडियाद, खेड़ा जिले में की गई थी।
- वित्तीय सेवाओं के अलावा आईपीपीबी, **बीमा जीवन, चिकित्सा और दुर्घटना सेवाएं**, आधार सेवाएं (मोबाइल नंबर अद्यतन) और पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
- डाक विभाग ने नागरिकों के लाभ के लिए पासपोर्ट और आधार सेवाएं प्रदान करने हेतु भी अपने व्यापक डाक नेटवर्क का प्रयोग किया है

- डाकघरों को पीओ-सीएससी के माध्यम से भारत में **ई-शासन सेवाएं** प्रदान करने का अवसर दिया गया है।
- **जी2सी सेवाओं में** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम एफबीवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि); प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम); प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम), राष्ट्रीय पेंशन योजना, पैन कार्ड ई-केवाईसी शामिल हैं।
- प्रदान की जाने वाली **बी2सी (व्यवसाय से नागरिकों को) सेवाओं में** भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल (बिजली, गैस,पानी के बिल आदि), जीवन बीमा पॉलिसियों और मोटर वाहन, स्वास्थ्य और अग्नि बीमा आदि जैसे सामान्य बीमा के नवीकरण हेतु प्रीमियम राशि एकत्रित करना शामिल है।

प्रतिभा खोज और पोषण का वर्तमान परिदृश्य

- प्रतिभा को एक प्राकृतिक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के साथ पैदा होती है।
- प्रतिभा को कौशल से अलग माना जाता है, जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अथवा सुधारा जा सकता है।
- प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और तत्पश्चात उन्हें सरकारी तंत्र के अंतर्गत लाकर उनका पोषण करने और उन्हें बढ़ावा देने की योजनाएं और कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
- भारत में, मुख्य रूप से दो धाराओं में प्रतिभा की खोज की जाती है: शैक्षणिक और खेल।

शैक्षणिक

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई):

- एनटीएसई प्रत्येक वर्ष दो स्तरों पर आयोजित की जाती है- स्टेज 1 (राज्य स्तर) और स्टेज 2 (राष्ट्रीय स्तर)।
- एनटीएसई चरण 1 का संचालन राज्यों द्वारा किया जाता है और एनटीएसई चरण 2 का संचालन एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है।
- कोई भी बच्चा, जिसने कक्षा 9 की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हैं, वह एनटीएसई चरण 1 परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है।
- एनटीएसई चरण 1 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित की जाने वाली चरण 2 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- एनटीएसई विद्वानों को भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए 1250 रुपये प्रति माह और स्नातक और उच्च अध्ययन के लिए 2000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

खेल

- **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीएसएस):** 8-12 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभा की पहचान करने और पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पोषण के लिए बनाई गई है। यह योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल:** यहां पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन दायर कर सकते हैं। तत्पश्चात पात्र युवाओं को खेल स्ट्रीम के आधार पर, चयन परीक्षणों के चिह्नित किए गए केंद्रों पर बुलाया जाता है।
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना :इस योजना के तहत, खेल के अच्छे बुनियादी ढांचे और विश्वसनीय खेल, प्रदर्शन रिकॉर्ड वाले विद्यालयों को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा अपनाया जाता है। यह योजना, तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों को, एक ही स्कूल में पढ़ने और खेलने का अवसर प्रदान करती है।
- एनएसटीसी की **इन उप-योजनाओं में** स्वदेशी खेल, मार्शल आर्ट (आईजीएमए) और अखाड़े शामिल हैं।
- **चयन मानदंडों** में राज्य / राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और चिकित्सकीय रूप से 'फिट' प्रतिभागी होने तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से 'फिट' प्रतिभागी होने के अलावा, विभिन्न परीक्षणों में उत्तीर्ण होना शामिल है।

- ऐसी खेल प्रतिभा खोज योजनाओं के **सुखद परिणाम** आने भी शुरू हो गए हैं जैसा कि हांगझांऊ में हाल ही में समाप्त हुए एशियाई खेलों में भारतीय दल द्वारा पदक तालिका में बेहतरीन प्रदर्शन से भी स्पष्ट होता है।
- **योजना की मुख्य कमियों को निम्नानुसार गिनाया जा सकता है:-**
    - खेलों की दृष्टि से बहुत अधिक **आयु लगभग 14-15 वर्ष** में प्रतिभाओं को चिह्नित किया जाता है, जबकि इस आयु तक वंचित समाज के बच्चों में से बहुत बड़ा प्रतिशत पहले ही स्कूल जाना छोड़ चुका होता है।
    - प्रतिभा खोज परीक्षा में **मानसिक क्षमता परीक्षण (एमएटी) और शैक्षिक योग्यता परीक्षा (एसएटी)** का ढांचा संरचनात्मक होता है और इससे कमजोर वर्गों से आने वाले और संकीर्ण सोच क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे नुकसान की स्थिति में रहते हैं।
    - चयनित विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों के साथ-साथ एनडीए में उपलब्ध कराए गए लाभ प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, रोजगार आदि प्रतिभा निखारने में कभी-कभार ही प्रेरणादायी सिद्ध होते हैं।

विकसित राष्ट्रों का अनुभव

- **संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फेडरल टीआरआईओ** कार्यक्रम समाज के वंचित पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्तियों की पहचान करते हैं और उनकी सहायता करते हैं जिनमें उच्च शिक्षा में सफल होने की क्षमता है।
- प्रतिभा खोज (टेलेंट सर्च) में उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होंने माध्यमिक या पोस्ट- माध्यमिक स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम पूरा नहीं किया है ताकि वे प्रवेश या पुनः प्रवेश कर पोस्ट माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें।
- **रूस की सरकार द्वारा 2014 में सोची में खोला गया सीरियस एजुकेशन सेंटर** खेल, कला और प्राकृतिक विज्ञान में उत्कृष्ट योग्यता वाले ग्रेड 5-11 के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए है। यह एक आवासीय स्कूल है जिसमें यात्रा, आवास, योजना और शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है।
- यदि हम इन दोनों देशों के अकादमिक प्रतिभा खोज और प्रतिभा को निखारने के कार्यक्रमों की तुलना करें, तो हम दोनों में निम्नलिखित मुख्य अंतर देख सकते हैं :-
    - संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलेंट सर्च प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बीच अकादमिक प्रतिभा की खोज करना और उसको निखारना है, जो अन्यथा उच्चतर अध्ययन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
    - सीरियस एजुकेशन सेंटर, सोची को कम आयु के प्रतिभाशाली बच्चों को चिह्नित करने और फिर उन्हें निःशुल्क शिक्षा, योजना आदि के माध्यम से निखारने के उद्देश्य से बनाया गया है।

भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार और जनसंख्या को देखते हुए, एक बहुत बड़े जनसंख्या आधार में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक विस्तृत फ़लक वाले प्रतिभा खोजतंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है और इसके बाद प्रतिभाशाली और जन्मजात प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जाए। ऐसे बच्चों को राज्यों के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में लाकर उनकी प्रतिभा को निखारा जाना चाहिए।

प्रतिभाओं से संपन्न ग्रामीण भारत

परिचय

- ग्रामीण भारत से निकली प्रतिभाएं आज अर्थतंत्र ही नहीं विज्ञान, तकनीक, कला एवं संस्कृति समेत हर क्षेत्र में अग्रणी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं की बदौलत ग्रामीण भारत से बदलाव के ऐसे वाहक सामने आए है, जो मानवीय जीवन के हर क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रामीण जीवनशैली सदियों से ज्ञान एवं नवाचार की पोषक रही है।
- छोटे शहर, कस्बे और गाँव में मौजूद तकनीक एवं नवोन्मेषी विचार आत्मनिर्भर भारत का आधार है। खेलों से लेकर ललित कलाओं में गाँव और कस्बाई क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने पदचिह्नों से नया भारत गढ़ रही हैं। इस बदलाव ने शहर और गाँव के बीच ज्ञान आधारित अंतर को न सिर्फ पाटने का काम किया है बल्कि ज्ञान, परंपरा, कौशल की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित किया है।

ग्रामीण भारत की प्रतिभाएं

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंद्रयान की सफलता पर बात करते हुए 'रॉकेट वुमन' ऋतु करिधाल के नाम का उल्लेख किया। लखनऊ के सामान्य परिवार में पली-बढ़ीं ऋतु चंद्रयान मिशन-3 की निदेशक हैं। इससे पहले वह मंगलयान मिशन की उप निदेशक रह चुकी हैं।
- आजमगढ़ के सठियांव ब्लॉक के रहने वाले युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा ने दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया है। किसान परिवार में जन्में योगेश्वर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उस टीम का हिस्सा है जिसने फास्ट लेजर सीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की खोज की है।
- पानीपत के लोहारी गाँव के डॉक्टर सुरेन्द्र सिंह ने कृषि अवशेष से कम्पोस्ट निर्मित करने वाले सूक्ष्मजीव की खोज की है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बुंदेलखंड के बंजर इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली गुरलीन चावला के नवाचार का जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात' कार्यक्रम में कर चुके हैं।

पंचायतों के नवाचार को मंच देता सरपंच संवाद

- पंचायती राज संस्थाएं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रारंभिक इकाई है। जमीनी स्तर पर होने वाले नवाचार सिर्फ उस गाँव, पंचायत एवं क्षेत्र तक सीमित न रहें, इसके लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद ने 'सरपंच संवाद ऐप' प्रस्तुत किया है।
- इस ऐप के जरिए देश के सभी सरपंचों को एक मंच पर लाया जा रहा है। इसमें सरंपच अपनी पंचायतों के विकास एवं किसी समस्या के समाधान से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। 'सरपंच संवाद' पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों में दक्षता संवर्धन को मजबूती देता है।

अटल इनोवेशन मिशन नवाचार की नर्सरी

- 2016 में शुरू किए गए अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के अंतर्गत स्थापित अटल टिंकरिंग (एटीएल) लैब छोटे शहरों और दूरदराज के गाँव में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए प्रयोगशाला की नर्सरी हैं।
- 700 जिलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 60 प्रतिशत लैब सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में हैं। अटल टिकरिग लैब में 12 लाख से अधिक नवाचार योजनाओं पर 75 लाख से अधिक विद्यार्थी संबद्ध होकर वैज्ञानिक समाधानों पर कार्य कर रहे हैं।
- एटीएल में 6वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3 डी प्रिंटिंग, फोटोटाइपिंग टूल, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिकी के बुनियादी अनुप्रयोग सीखते हैं।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस: नवोन्मेषी विचारों का मंच

- 1914 में स्थापित भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन (आईएससीए) देश के अलग-अलग क्षेत्रों की विज्ञान एवं नवाचार से जुड़ी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती है। इसके वार्षिक आयोजन विभिन्न शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों में होते हैं।
- 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस-2020 का थीम 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: ग्रामीण विकास' था। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 में दूरस्थ अंचल एवं आदिवासी समाज की वैज्ञानिक प्रथाओं व ज्ञान प्रणालियों पर केंद्रित 'आदिवासी विज्ञान कांग्रेस' का आयोजन किया गया।

इसरो ने स्कूली बच्चों के बीच बढ़ाई सहभागिता

- 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 में शुरू किया। इसमें 600 छात्रों ने अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की।
- अहमदाबाद में स्थापित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के जरिए इसरो समय-समय पर विज्ञान आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन देश के अलग-अलग हिस्से में करता रहा है।
- अंतरिक्ष विज्ञान का पालना कहे जाने वाले पीआरएल की 'विज्ञान एक्सप्रेस' निबंध प्रतियोगिताएं युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है।
- इसी क्रम में इसरो द्वारा 2019 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को विशेष वरीयता दी जाती है। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 'युविका' अनुसंधान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है।

ग्रामीण स्कूलों में पहुँच रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के ग्रामीण हिस्से में विज्ञान एवं गणित के विषयों पर अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है।
- तमिलनाडु सरकार ने 'थिरानारी थेरवू थिट्टम' योजना शुरू की। इस योजना में राज्य के ग्रामीण स्कूलों में छात्र-छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक्स विषय की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। आईआईटी, मद्रास इस योजना में विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन वाराणसी जिले के 100 गाँवों में ऑनलाइन माध्यम से मातृभाषा में विज्ञान एवं गणित की शिक्षा प्रदान कर रहा है।
- इसी क्रम में आईआईटी, मुम्बई ने ग्रामीण इलाकों में छात्राओं का रुझान विज्ञान विषयों की ओर बढ़ाने के लिए 'वूमन इन साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया' (वाइज) कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 9वीं कक्षा से ही छात्राओं को विज्ञान विषयों में पढ़ाई और अवसरों की जानकारी दी जाती है।
- भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संचालित इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी ऐप में 2000 से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं। इसकी पहुँच देश के 359 जिलों और 600 कस्बों तक है। ऐसे समग्र प्रयासों की बदौलत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 2021-22 में लड़कियों की नामांकन दर 21 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है।

छात्रवृत्ति एवं पुरस्कारों से प्रोत्साहन

- बच्चों के वैज्ञानिक नजरिए को समृद्ध करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च' (इंस्पायर) योजना शुरू की गई है। इसके तहत मानक (मिलियन माइंड्स ऑगमेटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज) पुरस्कार कार्यक्रम संचालित किया जाता है।
- वर्ष 2020-21 में इस कार्यक्रम को देश भर के 2 लाख से अधिक मध्य और उच्च विद्यालयों से 6.53 लाख विचार प्राप्त हुए। इसमें सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी विचारों को जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में प्रदर्शित करने के लिए चुना जाता है।
- साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ आईआईटी, मुंबई और आईआईटी, खड़गपुर ज्ञान आधारित साझेदारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम का हर साल आयोजन किया जाता है।
- गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, एकेडमिक एक्सिलेंस स्कॉलरशिप तथा डिफेंस सर्विस एकेडमिक स्कॉलरशिप शुरू की गई है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष जनजातीय समाज के 750 बच्चों को एम. फिल एवं पीएचडी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में वनवासी समाज के 20 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रति वर्ष विदेश में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

मानक क्लबों की स्थापना

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 2021-22 में स्कूलों में 1037 मानक क्लब स्थापित किए हैं। बीआईएस का उद्देश्य इन मानक क्लबों के माध्यम से कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण की अवधारणा से अवगत कराना है।

- मानक क्लबों के तत्वावधान में प्रश्नोत्तरी, मानक लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि गतिविधियों का संचालन भी शुरू किया गया है। स्कूलों में स्थापित मानक क्लब एक ओर जहां इन मानकों के विषय में जागरूकता लाने का कार्य करते हैं वहीं इनके पीछे की वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें परिचित कराते हैं।

खेलों के वैश्विक मानचित्र में ग्रामीण प्रतिभाएं

- चीन के होंगझोऊ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहली बार 100 से अधिक पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य) अपने नाम किए।
- उत्तर प्रदेश के मेरठ के इकलौता गाँव की पारुल चौधरी ने 5 हजार मीटर दौड़ और बहादुरपुर गाँव की अन्नू रानी ने 3 महिलाओं की भाला फेंक (जेवेलिन थो) प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता।
- मध्य प्रदेश के देवास के अमलताज गाँव की नेहा ठाकुर ने एशियाई खेल में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा (सेलिंग) में रजत पदक जीत देश को गौरवान्वित किया।
- फरीदाबाद के पृथला गाँव में पगडंडी में दौड़ लगाते हुए प्रीति लांबा ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर साबित कर दिया है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को यदि अवसर मिले तो आसमान मुट्ठी में कर सकती हैं।
- 'खेल' राज्य सूची का विषय है। ऐसे में ग्राम स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने में राज्यों की अहम भूमिका होती है।
- इंफाल (मणिपुर) में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 29 मार्च, 2022 तक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय 247 खेल अकादमियों को मान्यता प्रदान कर चुका है।
- 2018 से शुरू 'खेलो इंडिया' की योजनाओं के साथ ही राज्यों की विभिन्न खेल प्रतिभाओं को तराशने में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआइ) की अहम भूमिका है।
- बेंगलुरु, कोलकाता, गांधीनगर, मुंबई, भोपाल, सोनीपत, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी और इंफाल में स्थित क्षेत्रीय केंद्रों के अलावा 'साई' के अकादमिक केंद्र पटियाला, तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।
- 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए मलखम्ब, कालारीपयडू, थांग-ता, गतका, योगासन, सिलंबम जैसे प्राचीन खेलों को शामिल किया गया है।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल समेत कई सार्वजनिक उपक्रमों ने खेल संवर्धन बोर्ड स्थापित किए हैं।
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) योजना के तहत, प्रतिभाशाली बच्चों का चयन 8-14 आयु वर्ग में किया जाता है और उन्हें एसएआई केंद्रों में एक अच्छी तरह से संरचित प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।
- युवाओं को खेल में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर देने और उसे निखारने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

साहित्य सृजन में ग्रामीण प्रतिभाएं

- विज्ञान, खेल एवं लोककलाओं के साथ ही साहित्य सृजन में ग्रामीण भारत की प्रतिभाएं केंद्र में हैं। साहित्य अकादमी द्वारा युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा सम्मान दिया जाता है।
- वर्ष 2023 के लिए पुरस्कृत अनेक रचनाओं चाँदपुर की चंदा (हिंदी), तिरुकरतियल (तमिल), मन मोरा तोरा (कहानी), लले निलवाठ चाले न् जां (कविता) की विषयवस्तु ग्रामीण भारत और उसके सामाजिक सरोकार रहे हैं।

जनजातीय चित्रकला

- जनजातीय चित्रकला मुख्य रूप से आदिवासी सभ्यताओं व संस्कृति की प्रतिनिधि होती हैं।
- देश की प्रमुख जनजातीय चित्रकला में तंजौर, मधुबनी (बिहार), गोंड चित्रकला (मध्यप्रदेश), पट्टचित्र (ओडिसा), वरली चित्रकला (महाराष्ट्र), किवाड़ी चित्रकारी (राजस्थान) शामिल हैं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहल

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि उत्पादों से जुड़ी 82 तकनीकों का प्रसार किया जा रहा है। इसकी बदौलत किसान मेंथा, मीठी तुलसी, खस, जिरेनियम, लैवेंडर, काली हल्दी, काली अदरक से लेकर गुलदाउदी, गैलार्डिया जैसे फूलों की खेती के लिए आगे आए हैं।
- कृषि फसलों के साथ ही सीएसआईआर ने इत्र, रेडी टू इट फूड और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई तकनीक विकसित की है, जो गाँवों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचार कर रही हैं।

लोककलाओं को प्रोत्साहन

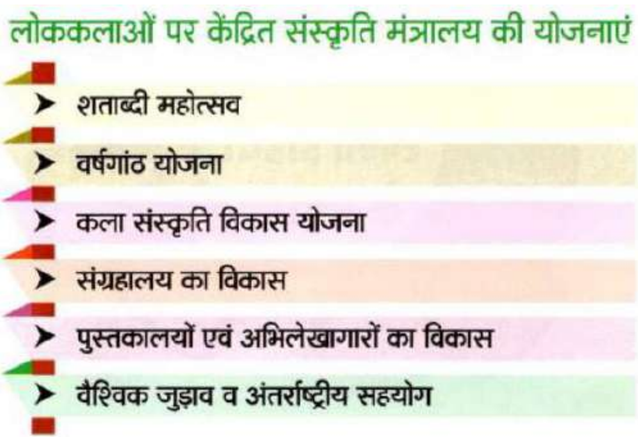

लोककलाओं पर केंद्रित संस्कृति मंत्रालय की योजनाएं

- शताब्दी महोत्सव
- वर्षगांठ योजना
- कला संस्कृति विकास योजना
- संग्रहालय का विकास
- पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास
- वैश्विक जुड़ाव व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में कला, संस्कृति एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है।
- स्थानीय लोककलाओं को बढ़ावा देने वाले 2015 से अब तक 12 राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय के सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सीसीआरटी) द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इनमें सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना काफी मददगार है।
- सीसीआरटी का मुख्य जोर स्कूली बच्चों में ललित कलाओं को लेकर छिपी प्रतिभा को निखारने का है। लोककलाओं को मिले ऐसे प्रोत्साहन से पुतलियों के निर्माण जैसी विलुप्त कलाएं पुनर्जीवित हो चुकी है।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा श्रीनगर, वड़ोदरा, गोवा, वाराणसी, त्रिशुर, पुडुचेरी, रांची, बेंगलुरु, गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में लोक कलाकारों पर केंद्रित सांस्कृतिक आयोजन के साथ पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

जनजातीय मंत्रालय की पहल

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) द्वारा जनजातीय समाज द्वारा तैयार किए गए आभूषण, वस्त्र व अन्य सहायक सामग्रियों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया जाता है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय की गो ट्राइबल पहल 700 जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सहायक साबित हुई है।
- जनजातीय समाज के नवाचार एवं उनकी जीवनशैली को संरक्षण एवं सवर्धन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।
- देशभर में स्थापित जनजातीय संग्रहालयों के जरिए आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय समाज की प्रथाओं के नवोन्मेषी उपायों के संवर्धन के लिए ट्राइबल डिजिटल डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी भी स्थापित की गई है।

निष्कर्ष

भारत प्राचीनकाल से स्थानीय ज्ञान का भंडार रहा है। ग्रामीण जनजीवन से निकली प्रतिभाएं एक बार फिर वैज्ञानिक और पर्यावरणीय समाधान प्रस्तुत करने के साथ ही खेलों एवं लोककलाओं के जरिए मानवीय जीवन को समृद्ध कर रही है। खास बात यह है कि ज्ञान एवं कौशल की इस विद्या की अगुआई युवाओं के हाथों में है।